मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 20.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 35,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 7.20 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 7,20,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

छ.ग. राज्य न्यायिक अकादमी के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 5.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 4

माननीय उच्च न्यायालय के अधिनस्थ न्यायालयों की स्थापना हेतु न्यायाधीशों के कुल 50 पदों के सृजन हेतु ₹ 2000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

जिला दुर्ग के तहसील मुख्यालय धमधा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 की स्थापना के लिए पदों के सृजन हेतु ₹ 28.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स	पद संख्या
1.	सिविल न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	लेवल-12	01
2.	स्टेनोग्राफर	लेवल-7	01
3.	प्रस्तुतकार	लेवल-7	01
4.	निष्पादन लिपिक	लेवल-4	01
5.	आदेशिका लेखक	लेवल-4	01
6.	साक्ष्य लेखक	लेवल-4	01
7.	आदेशिका वाहक	लेवल-1	01
8.	दफ्तरी कम फर्राश	लेवल-1	01

9.	भृत्य	लेवल-1	02
10.	चौकीदार	आकस्मिकता स्थापना	01
11.	वाटरमेन		01
12.	स्वीपर		01
कुल पद			**13**

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 20,28,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 5

अधीनस्थ न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 6

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 72.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 72,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 7

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 3.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 8

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट और पाक्सो के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 17.10 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 17,10,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 9

कॉमर्शियल कोर्ट के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 10

परिवार न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 3.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 11

परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 10,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 12

जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 1,50,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 13

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अंतर्गत नवीन जिला के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 14

विधि विभाग में पदस्थ न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 4.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,50,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीनस्थ 25 जिला प्राधिकरण एवं 65 तालुका समितियों एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के लिए कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 2,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 16

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत पदस्थ न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 27.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 27,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4070

मद क्रमांक 17

महाधिवक्ता कार्यालय बिलासपुर के कार्यालय उपयोग के लिए 02 नग ई-रिक्शा क्रय हेतु ₹ 4.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 4,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 64

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण क्रय हेतु ₹ 2.00 लाख तथा कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटरीकरण से संबंधित सामग्रियों के क्रय हेतु ₹ 3.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 5,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत विशेष न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके शासकीय/अधिग्रहित आवास गृह को सुसज्जित करने हेतु ₹ 9.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 9,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 1

जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवन निर्माण हेतु ₹ 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत जिला एवं अधिनस्थ न्यायालयों हेतु न्यायिक भवनों के निर्माण हेतु ₹ 4200.00 लाख का व्यय संभावित है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत जिला न्यायालय भवन, बिलासपुर में विक्रयकर कार्यालय के खुली भूमि में कोर्ट रूम, लाईब्रेरी, कांफ्रेंस हॉल, अधिवक्ताओं का बार रूम, अभियोजन कार्यालय एवं पार्किंगे निर्माण (अनुमानित लागत राशि रू. 36.83 करोड़) हेतु इस वर्ष ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: उक्त प्रयोजनों हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 55,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 2

उच्च न्यायालय के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 2500. 00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 25,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।

मद क्रमांक 3

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत न्यायिक अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बी टाईप-05, सी टाईप-06, डी टाईप-30, ई टाईप-25, एफ टाईप-30, जी टाईप-200, एच टाईप-400 एवं आई टाईप-400, कुल 1096 आवासीय भवन निर्माण का कुल लागत ₹ 16514.00 लाख अनुमानित है। इस वर्ष ₹ 6000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: इस प्रयोजन हेतु नवीन मद के रूप में ₹ 60,00,00,000 का प्रावधान किया गया है।